एफडीआई के जरिए प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस

● फॉर्च्यून-500 लिस्ट में शामिल कंपनियों से एफडीआई आकर्षित करने के लिए नई सरकार ने एफडीआई पॉलिसी 2023 भी की है लागू

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश को देश में निवेश के लिहाज से मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही योगी सरकार ने विशेषतौर पर प्रदेश में फॉर्च्यून-500 लिस्ट में शामिल ग्लोबल लीडिंग कंपनियों के निवेश को बढ़ाने के लिए हाल ही में बाकायदा नई फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई) पॉलिसी 2023 भी लागू कर दी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 14 फॉर्च्यून-500 एनलिस्टेड कंपनियों की उपस्थिति है। अब इस संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के एक प्रयास के तौर पर प्रदेश में एफडीआई को आकर्षित करने व यूपी को निवेश के लिहाज से देश का मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ)-2023 में योगी सरकार अपना प्रतिनिधिमंडल भी भेजने जा रही है।

अगले वर्ष जनवरी 15 से 19 के बीच डब्ल्यूईएफ में भाग ले रहे इस प्रतिनिधिमंडल में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) मनीज कुमार सिंह व सीएम के सचिव अमित सिंह भी शामिल होंगे। हाल ही में जापान की फूजी सिल्वरटेक कॉन्क्रीट प्राइवेट लिमिटेड वह पहली कंपनी बनी जिसने नई एफडीआई पॉलिसी लागू होने के बाद 1 अरब रुपए से अधिक का निवेशित निवेश किया है। फूजी सिल्वरटेक को विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए यीडा क्षेत्र के सेक्टर-32 में 75 प्रतिशत रियायती दरों पर 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यह स्थान आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) के पास है। इसके अतिरिक्त एक और फॉर्च्यून 500 कंपनी जिसे सब्सिडी वाली जमीन मिलने की उम्मीद है वह सिफी इनफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है जो सेक्टर-28 में डेटा सेंटर के विकास के लिए काम करेगी। इसी तरह स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करके सीएम योगी का प्रतिनिधिमंडल इन कंपनियों का एफडीआई माध्यम से व्यापक निवेश प्रदेश में आकर्षित कराने की कोशिश करेगा। वहीं अन्य वैश्विक आर्थिक मंचों पर भी उत्तर प्रदेश की व्यापक छवि प्रदर्शित करने की दिशा में भी योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में और तेजी लाने के लिए ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वैश्विक आर्थिक मंचों पर व्यापक उपस्थिति सुनिश्चित करने व वैश्विक दिग्गज कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संपर्क व समन्वय प्रक्रिया अपना रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में विदेशी निवेश आकर्षित करने में बड़ी प्रगति की है। 2001 से 2017 के बीच 17 सालों में जितना विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में आया, उससे करीब चार गुना ज्यादा विदेशी निवेश 2019 से 2023 के बीच सिर्फ पांच सालों में आया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग व भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया जबकि 2019 से जून 2023 के बीच सीधे तौर पर करीब 11000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। अक्टूबर 2019 से जून 2023 के बीच देश के विभिन्न राज्यों में एफडीआई लिस्ट में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश से ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल हैं।

वहीं उत्तर प्रदेश ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार, चंडीगढ़, गोवा और छत्तीसगढ़ समेत 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस आर्थिक वृद्धि को देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो जाएगा। हालांकि देश में आए कुल एफडीआई की अपेक्षा यह केवल 0.7 प्रतिशत था। साल 2014-15 में 679 करोड़ रुपए, 2015-16 में 524 करोड़ रुपए तथा साल 2016-17 में 50 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। ऐसे में उत्तर प्रदेश ने इसीलिए एफडीआई पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे इस अंतराल को पाटना होगा।

यूपी में 10 कंपनियां करेंगी 1.11 लाख करोड़ का निवेश

● प्रदेश सरकार कर रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पहले फेज की तैयारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के प्रथम फेज की तैयारी में जुटी हुई है। फरवरी में हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बाद अब तक यूपी को 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। वहीं जीबीसी के पहले फेज में सरकार और उद्यमी 13 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए तैयार हैं। प्रथम फेज में निवेश के मामले में जिन टॉप 10 कंपनियों की चर्चा हो रही है उनमें टाटा, हीरानंदानी, टस्को, ग्रीनको जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। ये कंपनियां प्रदेश के अंदर डेटा सेंटर, रिटेल मार्ट, स्किल डेवलपमेंट और ऊर्जा जैसे सेक्टर में निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जीबीसी के प्रथम फेज में प्रदेश में होने जा रहे सबसे बड़े निवेश की बात करें तो यह एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (हीरानंदानी) ग्रुप की ओर से गौतमबुद्ध नगर में डेटा सेंटर पार्क के निर्माण में होने जा रहा है। 30 हजार करोड़ का ये निवेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थापित करने की तैयारी है। वहीं 27 हजार करोड़ से अधिक का निवेश एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से किया जाना है। एनटीपीसी प्रदेश में ऊर्जा सेक्टर में दो संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है। इनमें एक झांसी में और दूसरा सोनभद्र में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सोनभद्र के ओबरा में सुपर थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. बोर्ड से अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही 17 हजार करोड़ से अधिक की परियोजना ग्रीनको कंपनी की ओर से सोनभद्र में स्थापित होने जा रही है। ऑफ स्ट्रीम क्लीज लूप पंप स्टोरेज परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार 8 हजार करोड़ की परियोजना सिफी इनफिनिट स्पेस लिमिटेड की ओर से धरातल पर उतारी जा रही है। ये प्रोजेक्ट आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जिसे नोएडा में डेटा सेंटर की स्थापना हो रही है। ये परियोजना निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 7500 करोड़ की परियोजना एम3एम इंडिया प्रा. लिमिटेड की ओर से नोएडा में लगने जा रही है। ये रियल स्टेट की परियोजना है। इसके लिए नोएडा के सेक्टर-94 में 52 हजार वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है। साथ ही रेरा से अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार टस्को लिमिटेड की ओर से 1 हजार मेगावाट की मालटीता फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना 6500 करोड़ की भी धरातल पर उतरने को तैयार है। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में इस पार्क की स्थापना होने जा रही है, जिसके लिए सभी अनुमतियां मिल चुकी हैं तथा परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है। वहीं बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड की ओर से 6 हजार करोड़ की परियोजना जालौन में धरातल पर उतरने जा रही है। इस परियोजना को भी भारत सरकार की एमएनआरई राष्ट्रीय सौर पार्क योजना के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।